# कारम बांध का बारिश से पहले होगा लोकार्पण

## साढ़े तीन साल पहले बारिश में घटिया निर्माण की वजह से फूट था

**भोपाल** मप्र के धार जिले के बहुचर्चित कारम बांध एक बार फिर बनकर तैयार हो रहा है। बांध का निर्माण अंतिम चरण में है। संभवत: बारिश से पहले बांध का लोकार्पण कर दिया जाएगा। बांध निर्माण में गुणवत्ता और सुरक्षा मानकों का ध्यान रखा गया है। निर्माण पूरा होने के बाद एक्सपर्ट कमेटी बांध की गुणवत्ता का निरीक्षण करेगी।

जल संसाधन विभाग के अपर मुख्य सचिव राजेश राजौरा ने बताया कि कारम बांध को 15 जून से पहले लोकार्पण करने जा लक्ष्य है। कार्य अंतिम चरण में है। निर्माण एजेंसी द्वारा लक्ष्य को ध्यान में रखाकर गुणवत्ता मानकों के तहत काम किया जा रहा है। बताया गया कि विभाग की विशेष टीम की निगरानी में निर्माण कार्य चल रहा है। उल्लेखनीय है कि अगस्त 2022 में बांध में क्षमता से ज्यादा पानी आने पर बांध फूट गया था। मानव त्रासदी रोकने के लिए बांध को किनारे से काटकर पानी खाली किया। निर्माण एजेंसी ने 45 एमसीएम क्षमता के बांध का अधूरा काम छोड़क़र बारिश में नाले को रोका गया था। बांध के डाउन स्ट्रीम में मौजूद 18 गांवों की आबादी को खतरे में डाला गया। बांध निर्माण में गुणवत्ता और मानकों का ध्यान नहीं रखा।

### 5 इंजीनियर इंजीनियर और ठेकेदार दोषी

जल संसाधन विभाग द्वारा दो महीने पहले फरवरी में कारम बांध फूटने की जांच रिपोर्ट में विभाग के 5 इंजीनियर और निर्माण एजेंसी दिल्ली की एएनएस कंस्ट्रक्शन कंपनी को दोषी ठहराया जा चुका है। जिम्मेदार ठहराया थ गया है। रिपोर्ट में बताया था कि 304 करोड़ की लागत वाले बांध के निर्माण में गुणवत्ता और मानकों की उपेक्षा की गई। बांध का फूटना सामान्य घटना नहीं थी, बल्कि बांध को बारिश में अपूर्ण छोड़क़र मानव निर्मित आपदा को निमंत्रण दिया गया था।

### विधानसभा में मंत्री ने रिपोर्ट के इतर दिया जवाब

विधानसभा के बजट सत्र में जल संसाधन मंत्री तुलसी सिलावट ने कारम बांध फूटन को लेकर कांग्रेस विधायक कालू सिंह ठाकुर द्वारा पूछे गए सवाल के जवाब में बताया कि बांध निर्माण में घटिया सामग्री का उपयोग नहीं हुआ। मंत्री का यह जवाब बांध फूटने की जांच रिपोर्ट के इतर था। क्योंकि रिपोर्ट में गुणवत्ता और मानकों का पालन नहीं करने का उल्लेख है।

# अमेरिका-ईरान के बीच शांति के लिए फिर शुरु होगी वार्ता, मध्यस्थता में जुटे कई देश?

**इस्लामाबाद (एजेंसी)।** इस्लामाबाद में अमेरिका और ईरान के बीच हुई हालिया उच्च स्तरीय वार्ता के बेनतीजा रहने के बाद, दोनों देश एक बार फिर मेज पर आमने-सामने बैठने की तैयारी कर रहे हैं।

हालिया अंतरराष्ट्रीय रिपोर्टों के अनुसार, मध्य पूर्व में बढ़ते तनाव को कम करने और एक स्थायी युद्धविराम समझौते पर पहुंचने के उद्देश्य से दोनों देशों के बीच पर्दे के पीछे राजनयिक संपर्क फिर से सक्रिय हो गए हैं। इस महीने की शुरुआत में हुआ अस्थायी युद्धविराम जल्द ही समाप्त होने वाला है, जिससे पहले एक ठोस समाधान खोजने का दबाव दोनों पक्षों पर बना हुआ है। रिपोर्टों के मुताबिक, इस्लामाबाद वार्ता विफल होने के बावजूद दोनों ही देशों ने संकेत दिए हैं कि बातचीत के रास्ते पूरी तरह बंद नहीं हुए हैं। अमेरिकी

उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने पाकिस्तान से विदा होते समय स्पष्ट किया था कि उन्होंने ईरान के सामने वाशिंगटन का अंतिम और सर्वोत्तम प्रस्ताव रख दिया है। हालांकि, ईरानी पक्ष ने उन शर्तों को तत्काल स्वीकार नहीं किया, जिसके कारण वार्ता का पहला दौर बिना किसी ठोस समझौते के समाप्त हो गया। अब चर्चा है कि दूसरे चरण की वार्ता भी इस्लामाबाद में ही आयोजित की जा सकती है, जहां पाकिस्तान मुख्य मध्यस्थ की भूमिका निभा रहा है। वर्तमान में पाकिस्तान के अधिकारी दोनों देशों के निरंतर संपर्क में हैं ताकि अस्थायी सीजफायर की अवधि समाप्त होने से पहले किसी स्थायी शांति समझौते पर मुहर लग सके। हालांकि, वाशिंगटन की सख्त शर्तों और तेहरान के अपने रुख पर अड़े रहने के कारण चुनौतियां बरकरार हैं। आने वाले कुछ दिन वैश्विक राजनीति और क्षेत्रीय शांति के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण माने जा रहे हैं, क्योंकि इसी पर तय होगा कि यह कूटनीतिक प्रयास युद्ध को रोकने में कितने सफल साबित होते हैं। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने सोमवार को इस संबंध में सकारात्मक संकेत देते हुए कहा कि अमेरिका और ईरान के बीच अगले दौर की वार्ता जल्द ही शुरू होने की उम्मीद है। 1979 की इस्लामी क्रांति के बाद यह पहला मौका था जब दोनों देशों के शीर्ष अधिकारियों ने सीधे तौर पर बातचीत में हिस्सा लिया। आसिफ ने संसद भवन के बाहर मीडिया से बात करते हुए कहा कि पिछले दौर की बातचीत के बाद एक तरह का संतोष है क्योंकि अब तक कोई नकारात्मक घटनाक्रम सामने नहीं आया है। उन्होंने इसे एक रचनात्मक दिशा में बढ़ता कदम बताया है।

## होर्मुज संकट के बीच चीन ने श्रीलंका को दिया दगा, भारत ने की आपातकालीन मदद

**नई दिल्ली (एजेंसी)।** होर्मुज संकट में जब चीन ने ईरान के साथ दोस्ती का ढोंग रचा और श्रीलंका से दगा किया तब भारत ने श्रीलंका का हाथ थाम लिया। ईंधन की कमी, आर्थिक दबाव और ऊर्जा संकट से जूझ रहे श्रीलंका को भारत ने आपातकालीन मदद पहुंचाई। अब श्रीलंका इस अहसान का बदला चुकाने जा रहा है। भारत की प्रमुख रक्षा शिपयार्ड मझगांव डॉक शिपबिल्डर्स लिमिटेड ने श्रीलंका के सबसे बड़े शिपयार्ड कोलंबो डॉकयार्ड पीएलसी में 51 फीसदी नियंत्रक हिस्सेदारी हासिल कर ली है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक यह सौदा एमडीएल का पहली अंतरराष्ट्रीय अधिग्रहण है, जिसकी कीमत 26.8 मिलियन डॉलर यानी करीब 249.5 करोड़ रुपए है। मुंबई स्थित इस डिफेंस पीएसयू ने 9 अप्रैल को जारी बयान में कहा था कि इस डील से श्रीलंका का सबसे बड़ा शिपयार्ड अब उसके परिचालन नियंत्रण में आ गया है। यह सौदा जापान की ओनोमिची डॉकयार्ड से शेयर खरीदकर पूरा हुआ है। यह अधिग्रहण सिर्फ व्यापारिक नहीं, बल्कि जियो पॉलिटिक्स के लिहाज से भी अहम माना जा रहा है। चीन श्रीलंका में हम्बनटोटा बंदरगाह पर 99 साल का पट्टा ले चुका है और कोलंबो में नियमित रूप से अपने नौसैनिक जहाज खड़े कर रहा है। भारतीय हिंद महासागर क्षेत्र में चीन की बढ़ती पैठ को देखते हुए दिल्ली इस अधिग्रहण को अपने समुद्री विस्तार रणनीति का हिस्सा बता रही है। रिपोर्ट के मुताबिक एमडीएल के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर (रिटायर्ड) कैप्टन जगमोहन ने कहा कि एमडीएल द्वारा सीडीपीएलसी का अधिग्रहण हमारे दोनों संगठनों के लिए ही नहीं, बल्कि भारत और श्रीलंका के बीच समुद्री सहयोग के लिए मील का पत्थर है। ईरान की अमेरिका-इजराइल से जंग के दौरान होर्मुज स्ट्रेट बंद होने से वैश्विक तेल और गैस आपूर्ति बुरी तरह प्रभावित हुई है। श्रीलंका जैसे छोटे देश ईंधन संकट, महंगाई और आर्थिक दबाव से जूझ रहे थे, जबकि चीन ने ईरान के साथ संबंधों का दावा किया, लेकिन व्यावहारिक रूप से श्रीलंका को तत्काल राहत नहीं दी।

# ताल-बेताला

शशिकांत गुप्ते,
मोबाइल नं.
78984-88217

## दिल की बात ...?

फिल्मी गीतकारों ने दिल (हृदय) अवयव को प्रतीक बनाके असंख्य गीत लिखें हैं। फिल्मी गीत अंतः कल्पनातीत ही होतें हैं। चालीस,पचास और साठ के दशक में बहुत से गीत सार गर्भित और प्रेरणा देने वालें भी लिखें गए हैं। संघर्ष मय जीवन को धैर्य प्रदान करने वाली निम्न पंक्तियों का स्मरण स्वाभाविक ही होता है। दुःख में जो गाए मल्हारें वो इंसान कहलाए

जैसे बंसी के सीने में छेद है फिर भी गाए
गाते गाते रोए मयूरा फिर भी नाच दिखाए रे
(फिल्म आशिक(1962) गीतकार हसरत जयपुरी)

आम जन की स्थिति भी आज बंसी जैसी हो गई है।

आमजन अनेक समस्याओं से घिरा होने के बाद भी धर्मांधता का शिकार होकर आश्वस्त है कि, .......है तो मुमकिन है।

यह तो हुई आमजन की स्थिति

विषयांतर को रोकते हुए,पुनः कल्पनातीत फिल्मी गानों की चर्चा करते हैं।

उक्त प्रकार के अनेक दार्शनिक गीत मिल जाएंगे। देश,काल और स्थिति के अनुसार परिवर्तन तो होना ही है। मानव जीवन में भौतिकवाद बढ़ने से तकरीबन सभी क्षेत्रों का व्यापारीकरण हो रहा है।

फिल्मों में दिल तोड़ने वाले,दिल चुराने,और दिल के टुकड़े टुकड़े करके मुस्कुराकर चल दिए। यह सुनकर सोचने में आता है कि इतनी निर्दयता के साथ कौन प्यार करता है? फिल्मों में प्रेमिका के लिए चांद सितारे तोड़कर लाने तक के जुमले नुमा आश्वासन दिए जातें हैं। टुकड़े टुकड़े शब्द फिल्मी दुनिया से निकलकर राजनीति के लिए उपयोगी हो गए हैं। देश के सर्वे सर्वा भी टुकड़े टुकड़े शब्द का इस्तेमाल चुनावी सभा में कर ही रहें हैं। एक व्यवहारिक प्रश्न उपस्थित होता है? कोई देश को बांटने का काम कर रहा है,और देश की कानून व्यवस्था निद्रा मग्न है? इन दिनों लोकतंत्र की बुनियाद असमति को बर्दाश्त नहीं किया जा रहा है। व्यवस्था की गलत नीतियों का विरोध करना देश द्रोह हो जाता है।सीबीआई और ईडी के द्वारा की जा रही कार्यवाही का अंजाम टांय-टांय फिस्स ही हो रहा है। विरोधियों के लिए असहमति प्रकट करने का अधिकार नहीं है,लेकिन सत्ता पक्ष के द्वारा विपक्ष के किसी भी सदस्य के लिए किसी भी तरह की अमर्यादित,और अशोभनीय भाषा का प्रयोग जायज हो जाता है। सच में राजनीति के गिरते स्तर को देखते हुए दिल के टुकड़े टुकड़े हो जातें हैं।

## 6000 से भी ज़्यादा चीज़ों का आधार है क्रूड ऑयल

**नई दिल्ली ।** हाल ही में अमेरिका और ईरान के बीच शांति वार्ता के बेनतीजा रहने के बाद वैश्विक स्तर पर कच्चे तेल की आपूर्ति और कीमतों को लेकर चिंताएं बढ़ा दी हैं। आमतौर पर हम सभी यही जानते हैं कि क्रूड ऑयल का इस्तेमाल मुख्य रूप से पेट्रोल, डीज़ल और मिट्टी का तेल जैसे ईंधनों को बनाने के लिए होता है। हालांकि, यह जानकारी अधूरी है। विशेषज्ञों के मुताबिक, कच्चा तेल सिर्फ इन गिने-चुने उत्पादों तक सीमित नहीं है, बल्कि यह हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इस्तेमाल होने वाली 6000 से भी ज़्यादा चीज़ों का आधार है। यूएस एनर्जी इन्फॉर्मेशन एडमिनिस्ट्रेशन (ईआईए) की एक रिपोर्ट के अनुसार, कच्चे तेल का सबसे बड़ा हिस्सा ज़रूर ईंधन उत्पादन में जाता है, जिसमें पेट्रोल, डीज़ल, केरोसीन, एलपीजी और एविएशन फ्यूल जैसे महत्वपूर्ण ऊर्जा स्रोत शामिल हैं। ये ईंधन न केवल हमारे वाहनों को गति देते हैं, बल्कि उद्योगों और विमानन क्षेत्र के लिए भी अत्यंत आवश्यक हैं।

## हमेशा शांति के लिए तैयार भारतीय सेना, सात समंदर पार भी निभाई जिम्मेदारी

**नई दिल्ली।** पूरी दुनिया में जब भी जहां भी शांति और सुरक्षा की बात आती है, तब भारतीय सैनिकों का नाम सबसे ऊपर आता है। अपनी बहादुरी और अनुशासन के दम पर भारतीय सेना न केवल देश की सरहदों की रक्षा कर रही है, बल्कि सात समंदर पार भी अशांत इलाकों में शांति का झंडा बुलंद कर रही है। खतरनाक जंग के मैदान हों या गृहयुद्ध से जूझते देश, भारतीय सैनिक हर जगह अपनी जिम्मेदारी बखूबी निभा रहे हैं। बात दें कि भारत की विदेश नीति हमेशा से वैश्विक शांति की समर्थक रही है। इसकारण संयुक्त राष्ट्र (यूएन) के शांति मिशनों में भारत सबसे ज्यादा सैनिक भेजने वाले देशों में शामिल है। भारतीय सैनिक उन इलाकों में तैनात होते हैं, जहां हिंसा चरम पर होती है या दो देशों के बीच युद्ध जैसी स्थिति बनी रहती है। इन मिशनों का मुख्य उद्देश्य युद्धविराम को लागू करना, स्थानीय नागरिकों को उग्रवादियों से बचाना और संघर्ष प्रभावित क्षेत्रों में फिर से जीवन को सामान्य बनाना है। लेबनान में वर्तमान में इजरायल लोगों को निशाना बना रहा है। इस समय में वहां पर भारतीय सैनिकों की भूमिका बेहद चुनौतीपूर्ण और संवेदनशील है। यहां इजरायल और हिजबुल्लाह के बीच लगातार तनाव बना रहता है। यूएन मिशन (यूएनआईएफआईएल) के तहत भारत ने यहां लगभग 600 सैनिकों की एक बड़ी टुकड़ी तैनात की है।

### होर्मुज स्ट्रेट पर अमेरिकी दादागीरी के चलते

# दुनिया में मचेगा तेल को लेकर हाहाकार

**वॉशिंगटन ।** अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की घोषणा के बाद अमेरिकी नौसेना सोमवार से ही इस सामरिक जलमार्ग पर ईरानी बंदरगाहों की ओर जाने वाले और वहां से आने वाले जहाजों की आवाजाही पर रोक लगाएगी।

इस फैसले के बाद खाड़ी क्षेत्र में सैन्य संघर्ष की आशंका तेज हो गई है, जिसका सीधा असर वैश्विक तेल आपूर्ति पर पड़ सकता है।यूएस सेंट्रल कमांड द्वारा जारी बयान के अनुसार, अमेरिकी बल ईरानी बंदरगाहों और तटीय क्षेत्रों में आने-जाने वाले सभी देशों के जहाजों की

नाकेबंदी शुरू कर देंगे। यह आदेश अरब की खाड़ी और ओमान की खाड़ी के सभी ईरानी बंदरगाहों पर निष्पक्ष रूप से लागू होगा। हालांकि, अमेरिका ने स्पष्ट किया है कि होर्मुज से गैर-ईरानी बंदरगाहों की ओर जाने वाले जहाजों को बाधित नहीं किया जाएगा। नाविकों को सलाह दी गई है कि वे अमेरिकी नौसेना के संपर्क में रहें और सुरक्षा निर्देशों का पालन करें। यह कड़ा फैसला पाकिस्तान में हुई उस द्विपक्षीय वार्ता के विफल होने के बाद आया है, जिसमें दोनों देश परमाणु हथियारों के मुद्दे पर किसी सहमति पर नहीं पहुंच सके थे। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया पर अपने कड़े रुख को स्पष्ट करते हुए कहा कि ईरानी प्रशासन को पैसा और परमाणु हथियार चाहिए, जिसे अमेरिका किसी भी कीमत पर स्वीकार नहीं करेगा।

## कोर्ट की शरण में गए 2000 संविदा कर्मियों की नौकरी खतरे में

### कॉन्ट्रैक्ट का नहीं होगा नवीनीकरण, अब अदालत जाना भी सजा का कारण?

**भोपाल (एजेंसी)।** मध्य प्रदेश में करीब 2000 संविदा कर्मियों के सामने नौकरी पर संकट खड़ा हो गया है। जानकारी के अनुसार, जिन कर्मचारियों ने अपने सेवा संबंधी मुद्दों को लेकर अदालत का रुख किया है, उनके कॉन्ट्रैक्ट के नवीनीकरण पर रोक लगाने की तैयारी की जा रही है। संबंधित विभागों ने संकेत दिए हैं कि कोर्ट में प्रकरण दर्ज कराने वाले कर्मियों के अनुबंध रिन्यू नहीं किए जा सकते। इस फैसले से संविदा कर्मचारियों में नाराजगी बढ़ गई है। उनका कहना है कि न्याय के लिए अदालत जाना उनका संवैधानिक अधिकार है, और इसे सजा का आधार नहीं बनाया जाना चाहिए। कर्मचारी संगठनों ने इसे दबाव की कार्रवाई बताते हुए सरकार से निर्णय पर पुनर्विचार की मांग की है। वहीं, प्रशासन का पक्ष है कि अनुबंध नवीनीकरण प्रक्रिया नियमों के तहत होती है। मामले को लेकर कानूनी और प्रशासनिक बहस तेज हो गई है।

# ईरानी बंदरगाहों की नाकेबंदी से भड़का चीन कहा- हमारे काम में दखल न दे अमेरिका

**बीजिंग (एजेंसी)।** होर्मुज के बहाने ईरान को चारों तरफ से अमेरिका घेरने में लगा हुआ है। इसी घेराबंदी के चलते उसने ईरानी बंदरगाहों की नाकेबंदी कर दी। इससे चीन भड़क गया है और अमेरिका को सख्त चेतावनी देते हुए कहा है कि हमारे काम में किसी भी तरह दखल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।

चीन का यह बयान ऐसे समय पर सामने आया है, जब स्ट्रेट ऑफ होर्मुज से चीन के जहाजों को वापस लौटना पड़ा। पाकिस्तान में हुई ईरान के साथ वार्ता फेल होने के बाद राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने नाकेबंदी के आदेश दिए थे। बता दें कि अमेरिका-ईरान वार्ता के विफल रहने और नाकेबंदी की घोषणा के बाद तेल कीमतों में तेज उछाल देखा गया। ब्रेंट क्रूड 101.88 डॉलर प्रति बैरल और अमेरिकी क्रूड 104.69 डॉलर प्रति बैरल तक पहुंच गया। विश्लेषकों का मानना है कि होर्मुज पर तनाव की आशंका के चलते दुनिया के एनर्जी मार्केट में अस्थिरता बनी रह सकती है।

चीन के रक्षा मंत्री डोंग जुन ने कहा कि उनका देश क्षेत्र में शांति और स्थिरता के पक्ष में है, लेकिन वह ईरान के साथ अपने ऊर्जा और व्यापार समझौतों का सम्मान करेगा और अपने हितों में किसी बाहरी दखल को स्वीकार नहीं करेगा। चीन ने इस बात पर जोर दिया है कि स्ट्रेट पर ईरान का नियंत्रण है और यह जलमार्ग चीन के लिए खुला रहेगा। उन्होंने कहा, हमारे जहाज स्ट्रेट ऑफ होर्मुज के पानी में आ और जा रहे हैं। ईरान के साथ हमारे व्यापार और ऊर्जा के समझौते हैं। हम उन समझौतों का सम्मान करेंगे और उन्हें निभाएंगे, और हम उम्मीद करते हैं कि दूसरे हमारे मामलों में दखल नहीं देंगे।

### स्पेन,आस्ट्रेलिया जैसे देशों में नाराजगी

स्पेन की रक्षा मंत्री मार्गरीटा रोब्लेस ने नाकेबंदी की चेतावनी को बेमतलब करार देते हुए कहा कि यह संघर्ष पहले ही दुनिया को एक खतरनाक स्थिति में ले जा चुका है। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बानीज ने कहा कि उन्हें नाकेबंदी में शामिल होने के लिए कोई अनुरोध नहीं मिला है और जलमार्ग सभी देशों के लिए खुला रहना चाहिए।

### ईरान ने कहा तो ध्वस्त कर देंगे बंदरगाह

वहीं दूसरी तरफ जवाब में ईरान ने फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी के सभी बंदरगाहों को निशाना बनाने की धमकी दी। इससे दोनों पक्षों के बीच युद्ध-विराम के विफल होने और लड़ाई फिर से छिड़ने की आशंका बढ़ गई है।

समुद्री सुरक्षा की निगरानी करने वाली यूनाइटेड किंगडम मैरीटाइम ट्रेड ऑपरेशंस एजेंसी ने नाविकों के लिए एक नोटिस जारी किया, जिसमें कहा गया है कि नाकेबंदी में बंदरगाहों और ऊर्जा बुनियादी ढांचे सहित पूरी ईरानी तटरेखा शामिल है। इसमें कहा गया है कि गैर-ईरानी ठिकानों से आने वाले या वहां जाने वाले जहाजों के लिए स्ट्रेट से गुजरने पर प्रतिबंध नहीं होने की खबरें हैं।

## कार्टून कोना....

स्वामी मेसर्स एसोसिएटेड प्रिंटर्स एण्ड पब्लिशर्स (एम.पी.) प्रा.लि. इंदौर के लिए मुद्रक एवं प्रकाशक मोनिका सेठ द्वारा 17, न्यू देवास रोड (संजय गांधी मार्ग) इंदौर से मुद्रित एवं 5, प्रेस कॉम्प्लेक्स, इंदौर से प्रकाशित संपादक-मोनिका सेठ,
फोन नं. 3551753, 2434701, 2544433, समाचार पत्र से प्रकाशित समाचार के लिए सभी विवादों का न्याय क्षेत्र इंदौर रहेगा। समाचार चयन के लिए पी.आर.बी. एक्ट के तहत जिम्मेदार*